Construction of marine drive road in Orissa

1301. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is a need to construct a wide marine drive road between Konark and Puri in Orissa;

(b) if so, what steps had been taken in this regard and the progress made therein;

(c) whether Government have a proposal to connect all the important sea beaches in Orissa by marine drive road; and

(d) if so, the proposal mooted in this direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d) The Central Government is responsible for Roads declared as National Highways only. All roads other than National Highways are essentially the responsibility of the respective State Governments. The roads in question being State Roads, their construction/development/maintenance etc. is the responsibility of the State Government of Orissa.

Capital Dredging at Jiggerkhali Flat

1302. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the reply to Unstarrred Question 4044 given in the Rajya Sabha on 24th August, 1994 and state:

(a) whether the defaulting Dutch Contractor engaged by Calcutta Port Trust is now showing interest in Resuming the work; if so, under what conditions;

(b) whether Government have taken any decision in this regard;

(c) in point (e) of the reply to above referred question, whether the intensive maintenance dredging at Balary region is an alternative to Capital Dredging at Jiggerkhali Flat; and

(d) if so, the details of the quantities of spoil estimated to be lifted in both the cases?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir. It will be governed under the conditions of the Cooperation agreement. No specific conditions have been laid by the Contractor.

(b) No, Sir.

(c) and (d) No, Sir. The recessional dredging at Jiggerkhali Flat envisages deployment of one cutter suction dredger whilst the intensive maintenance dredging envisages deployment of two cutter suction dredgers following the ebb and flood tracks in Balari/Haldia channel in tune with the natural propensities in this channel (.)

The total quantity of spoil to be lifted in the intensive maintenance dredging project is of the order of 2.3 M.C.M as against 10.8 M.C.M. projected for the recessional dredging at Jiggerkhali Flat.

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव

1303. श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और राजस्थान सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के राजमार्गों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रेषित प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों की स्थिति क्या है ;

(ग) उक्त प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय सहायता निधि से उक्त प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशियां आवंटित की गई हैं;

(घ) क्या कुछ अनुमोदित परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) भारत सरकार मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित प्रस्तावों के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

राज्य	1991-92			1992-93			1993-94		
	प्राप्त हुए	संस्वीकृत	वापस भेजे गए	प्राप्त हुए	संस्वीकृत	वापस भेजे गए	प्राप्त हुए	संस्वीकृत	वापस भेजे गए
गुजरात	68	40	28	37	14	23	42	29	13
महाराष्ट्र	83	53	30	43	31	12	77	40	37
मध्य प्रदेश	43	20	23	33	13	20	15	2	13
राजस्थान	54	28	26	28	11	17	17	3	14

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन परियोजना-वार नहीं बल्कि राज्य-वार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया आबंटन निम्न प्रकार है :—

(लाख रु०)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
गुजरात	4770	4650	6350
महाराष्ट्र	3358	3280	3080
मध्य प्रदेश	1850	1915	1850
राजस्थान	1800	3095	4200

(घ) और (ङ) भूमि अधिग्रहण के मामले में धीमी प्रगति, संविदा संबंधी समस्याओं, वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है ।

समुद्री मार्ग से विदेशी माल की तस्करी

1304. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अन्नतराम जायसवाल :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री मार्ग से विशेषत: कलकत्ता बन्दरगाह से बड़े पैमाने पर विदेशी माल की तस्करी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या समुद्री मार्ग से माल की तस्करी होती रहेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या प्रभावी और तात्कालिक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा

1305. **श्री राघवजी** :क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1994 में भारी वर्षा के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष अनुदान आवंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अनुदान दे दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह अनुदान कब तक दे दिया जाएगा ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सांविधानिक दृष्टि से भारत सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी अनिवार्यत: संबंधित राज्य सरकार की होती है। मध्य प्रदेश राज्य सहित अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में वर्ष 1994 के लिए, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत हेतु, अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं। तथापि, क्षति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तुरन्त मरम्मत के लिए 25.00 लाख रु0 की राशि तदर्थ आधार पर पहले ही जारी की जा चुकी है। क्षति को ध्यान में रख कर संस्वीकृत किए जाने वाले प्राक्कलनों और निधियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर ही और निधियां जारी की जायंगी।

Unloading capacity of cargo

1306. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any survey has been conducted by Government to find out the unloading capacity of cargo vis-a-vis the required capacity at different ports during the last three years;

(b) if so, the details of the required capacity and the actual capacity;

(c) what measures are contemplated to reduce this gap between the actual capacity and the required capacity of unloading cargo in each port for the last three years;